(c) the number of workers who have been retrained *so* far?

TOE MINISTER OF STATE IN THE M©BSTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) The National Renewal Fund has been set up by Government to provide a social safety net to workers affected by modernisation, technology upgradation and industrial restructuring of industrial units. It would, *inter-alia,* provide for workers* compensation payments, counselling, retraining and redeployment of rationalised workers. Assistance from the National Renewal Fund has been made available to Central Public Sector Undertakings for implementation of the Voluntary Retirement Scheme, as well as for worker retraining/redeployment scheme*.

(to) Five Employee Assistance Centres had been set up initially under the National Renewal Fund for undertaking activities relating to counselling, retraining and redeployment of rationalised workers. Similar facilities have been extended by Ministry of Labour through six Advanced Training Institutes and 15 Industrial Training Institutes. 30 additional locations have been identified recently for setting up of Employee Assistance Centres.

(e) As on 28-2-1995, 1015 rationalised workers have been imparted retraining at the five Employee Assistance Centres.

Estimated motor CERS available *to* public

702. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether Government have estimated the actual number of motor cars> to be made available to Indian public by the end of the century.

(b) whether Indian road conditions are preventing the new car projects *to come up;* and

(c) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI: (a) No specific estimate has been made by Govt, regarding production of cars.

(b) and (c) Judging by the response from major global car manufacturers for tie-ups in India, it does not appear that Indian road conditions *are* preventing new investments in car projects.

उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी किया जाना

703. प्रो० राम लखन सिंह वर्मा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं :

(ख) इन लाइसेंसों को जारी किए जाने के संबंध में तिथिवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा आठवीं-पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत वर्ष 1992

से 1994 तक के वर्षों के दौरान कुल 404 औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थ । उनमें से उत्तर प्रदेश का अंश 51 है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**) ।

(ग) किसी राज्य में पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को स्थापित करने के लिए कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है । फिर भी, देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष 1988 में एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की गई थी। योजना के तहत 70 विकास केन्द्र जिनमें प्रत्येक में केन्द्र राज्य तथा वित्तीय संस्थाओं से भागेदारी के साथ लगभग 30 करोड़ रुपये का निवेश निहित है

विवरण

वर्ष 1992-1993 तथा 1994 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों (आई० एल०) का राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	4	3
2.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
3.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
4.	असम	2	—	—
5.	बिहार	1	1	1
6.	चण्डीगढ़	—	—	—
7.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—	—
8.	दमन तथा दीव	—	1	1
9.	दिल्ली	2	—	—
10.	गोआ	2	4	1
11.	गुजरात	23	21	22
12.	हरियाणा	7	7	8
13.	हिमाचल प्रदेश	—	1	1

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992	1993	1994
1	2	3	4	5
14.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—	—
15.	कर्नाटक	8	5	8
16.	केरल	—	3	3
17.	लक्षद्वीप	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	6	2	2
19.	महाराष्ट्र	29	23	34
20.	मणिपुर	—	—	—
21.	मेघालय	—	—	—
22.	मिजोरम	—	—	—
23.	नागालैण्ड	—	—	—
24.	उड़ीसा	1	1	2
25.	पांडिचेरी	2	—	—
26.	पंजाब	10	4	6
27.	राजस्थान	1	1	2
28.	सिक्किम	—	—	—
29.	तमिलनाडु	18	20	22
30.	त्रिपुरा	—	—	—
31.	उत्तर प्रदेश	14	16	21
32.	पश्चिमी बंगाल	2	3	2
33.	जो दर्शाए नहीं गए/ एक राज्य से अधिक	1	3	5
	कुल	140	120	144